# राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

डी.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 94/2020

श्रवण मांझी पुत्र रामदेव मांझी, निवासी मांझी का मोहल्ला, खरारी, जिला दरभंगा (बिहार)। (वर्तमान में ओपन एयर कैंप, गंगानगर में आवासित)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य, सचिव, गृह विभाग, जयपुर के माध्यम से।

2. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, श्री गंगानगर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: डाक द्वारा

प्रतिवादी के लिए: श्री फरजंद अली जीए-सह-एएजी

श्री अभिषेक पुरोहित के सहयोगी

**माननीय न्यायाधिपति संदीप मेहता**

**माननीय न्यायाधिपति कुमारी प्रभा शर्मा**

**<u>आदेश</u>**

घोषणा की तिथि : 25/08/2020

रिजर्व की तिथि : 19/08/2020

**<u>रिपोर्टेबल</u>**

ओपन एयर कैंप, श्री गंगानगर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी याचिकाकर्ता श्रवण मांझी द्वारा तत्काल रिट याचिका दायर की गई है। जवाब में दिए गए हिरासत विवरण के अनुसार, दोषी ने लगभग 17 साल की वास्तविक सज़ा काटी है और लगभग 3.5 साल की छूट अर्जित की है।

रिकॉर्ड और जवाब से यह एक स्वीकृत स्थिति सामने आ रही है कि दोषी ने अपनी कैद की अवधि के दौरान नियमित पैरोल का संतोषजनक ढंग से लाभ उठाया है और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि दोषी ने एक से अधिक अवसरों पर उसे दी गई स्वतंत्रता का

दुरुपयोग किया हो। दोषी ने अपेक्षित कारावास की सजा काट ली, जिसके बाद वह स्थायी पैरोल मांगने का हकदार बन गया, जिसके बाद उसने राज्य स्तरीय पैरोल सलाहकार समिति के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसने निम्नलिखित कारण बताते हुए इसे खारिज कर दिया:-

> "6. द.ब. श्रवण मांझी पुत्र रामदेव मांझी, जाति-मांझी मल्लाह, निवासी- खरारी, पुलिस थाना - हायाघाट, जिला - दरबंगा (बिहार) (ब.खु.शि. श्रीगंगानगर ):- बंदी को माननीय सैशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़ द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 20/2004 (39/2003) अंतर्गत धारा 364, 376 (2) (एफ), 377, 302, 201 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 16.07.2004 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा अपहरण, बलात्कार जैसा जघन्य, वीभत्स अपराध कारित किया गया है, अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी श्रवण मांझी पुत्र रामदेव मांझी को स्थाई पैरोल पर रिहा नहीं करने की अनुशंषा की है। राज्य सरकार राज्य स्तरीय पैरोल समिति की अभिशंषा से सहमत है। अतः बंदी को

स्थाई पैरोल  पर रिहा नहीं करने का निर्णय लिया गया है"।

दोषी ने अब उपरोक्त सिफारिशों पर हमला करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस पत्र रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस पत्र रिट याचिका में दोषी की ओर से यह प्रार्थना भी की गई है कि उसे निजी मुचलका जमा करने पर ही स्थायी पैरोल दी जानी चाहिए क्योंकि उसकी बीमार पत्नी और दो नाबालिग बच्चों के अलावा, परिवार में कोई और नहीं है जो दोषी की ओर से जमानत दे सके, अगर उसे स्थायी पैरोल पर रिहा किया जाता है।

अपने जवाब में, उत्तरदाताओं ने प्रतिकूल सिफारिशों का समर्थन किया है जिसके तहत वर्तमान याचिकाकर्ता के स्थायी पैरोल आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

दिनांक 06.07.2018 की सिफारिशों के उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफ के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को स्थायी पैरोल से इनकार करने का एकमात्र कारण अपराध की जघन्यता और गंभीरता है। अवधि के दौरान जेल में दोषी-याचिकाकर्ता के आचरण पर कोई विचार नहीं किया गया, उसने नियमित पैरोल की सुविधा का लाभ उठाया।

पैरोल की अवधारणा के पीछे का उद्देश्य सजा के सुधारात्मक सिद्धांत के अनुरूप है और यह एक सुधारात्मक उपाय के रूप में एक दोषी को उसके पुनर्वास और समाज में पुनः शामिल होने का अवसर प्रदान करने का एक साधन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एआईआर 2017 एससी 4986 में रिपोर्ट किए गए असफाक बनाम राजस्थान राज्य के मामले में इस सिद्धांत पर विस्तृत विचार किया, जिसमें इसे निम्नानुसार रखा गया था: -

> "7) हम शुरू में कह सकते हैं कि जिस कारण से उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया वह उचित नहीं है और कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। **याचिका केवल इस आधार पर खारिज की जाती है कि अपीलकर्ता को गंभीर और जघन्य अपराध के मामले में दोषी ठहराया गया है और इसलिए, पैरोल का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद होने वाली चर्चा के अनुसार, किसी गंभीर और जघन्य अपराध में दोषसिद्धि पैरोल से इनकार करने का कारण नहीं हो सकती।** उच्च न्यायालय द्वारा की गई एक और टिप्पणी यह है कि चूंकि इस न्यायालय ने अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि

करते हुए उसकी अपील पर निर्णय लिया था, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए अपीलकर्ता के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करना उचित नहीं होगा और यदि वह चाहे तो उक्त उद्देश्य के लिए इस न्यायालय से संपर्क कर सकता है। यह फिर से उच्च न्यायालय में निहित शक्ति का त्याग है। जहां तक उस अपराध के लिए दोषसिद्धि का सवाल है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था, यानी टाडा के प्रावधानों के तहत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय तक इसे बरकरार रखा गया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय के समक्ष मामला पूरी तरह से अलग था। बात यह थी कि क्या अपीलकर्ता बीस दिनों के लिए पैरोल देने का हकदार है, जिसका वह दावा कर रहा था। केवल इसलिए कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का मामला इस न्यायालय में आया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अपीलकर्ता को हर बार इस न्यायालय में वापस जाना होगा, तब भी जब वह मुख्य दोषसिद्धि से असंबद्ध राहत की मांग कर रहा हो। ऐसा तब और अधिक होता है जब प्रथम दृष्टया उच्च न्यायालय को ही अपीलकर्ता द्वारा पैरोल के लिए की गई ऐसी प्रार्थना पर

निर्णय करना होता है। इन टिप्पणियों के साथ, हम मौजूदा मुद्दे की ओर ध्यान दिलाते हैं।

8) सबसे पहले पैरोल देने का मतलब और उद्देश्य समझना जरूरी होगा। फर्लो के विपरीत विचार करने पर इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। इन शर्तों को समय-समय पर न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से परिभाषित और न्यायिक रूप से समझाया गया है।

9) पैरोल और फर्लो के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। पैरोल को कैदियों की सशर्त रिहाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है यानी किसी कैदी की शीघ्र रिहाई, अच्छे व्यवहार की शर्त और एक निर्धारित अवधि के लिए अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट करना। इसे सशर्त क्षमा के एक रूप के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा दोषी को उसकी सजा की समाप्ति से पहले रिहा कर दिया जाता है। इस प्रकार, पैरोल अच्छे व्यवहार के लिए इस शर्त पर दी जाती है कि पैरोलकर्ता नियमित रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। पैरोल पर कैदी की ऐसी रिहाई कुछ बुनियादी आधारों पर अस्थायी तौर पर भी

हो सकती है। उस स्थिति में, इसे सजा की मात्रा को बरकरार रखते हुए कुछ समय के लिए सजा का निलंबन मात्र माना जाएगा। पैरोल पर रिहाई को कुछ निर्दिष्ट अत्यावश्यकताओं में कैदियों को कुछ राहत देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसी पैरोलें आम तौर पर कुछ स्थितियों में दी जाती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हो सकती हैं:

(i) कैदी के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या वह गंभीर रूप से बीमार है या कैदी खुद गंभीर रूप से बीमार है;

या

(ii) स्वयं कैदी, उसके बेटे, बेटी, पोते, पोती, भाई, बहन, बहन के बेटे या बेटी का विवाह मनाया जाना है; या

(iii) कैदी की अस्थायी रिहाई उसकी भूमि या उसके पिता की अविभाजित भूमि जो वास्तव में कैदी के कब्जे में है, की जुताई, बुआई या कटाई या किसी अन्य कृषि कार्य को करने के लिए आवश्यक है; या

(iv) किसी अन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करना वांछनीय है;

(v) सजा का एक हिस्सा पहले ही काट लेने के बाद ही पैरोल दी जा सकती है;

(vi) यदि पैरोल की शर्तों का पैरोल द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उसे जेल में अपनी सजा काटने के लिए वापस किया जा सकता है, ऐसी शर्तें एक नया अपराध करने जैसी हो सकती हैं; और

(vii) दोषी के स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं के आधार पर भी पैरोल दी जा सकती है।

12) एक दोषी को, शाब्दिक रूप से, सजा की अवधि के लिए या आजीवन कारावास की स्थिति में शेष जीवन के लिए जेल में रहना चाहिए। इस संदर्भ में, थोड़े समय के लिए जेल से उनकी रिहाई को न केवल अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को हल करने के लिए बल्कि समाज के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए एक अवसर के रूप में माना जाना चाहिए। **दोषियों को भी कम से कम कुछ समय के लिए ताजी हवा में सांस लेनी चाहिए, बशर्ते वे कारावास के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखें और खुद को सुधारने और अच्छे नागरिक बनने की प्रवृत्ति दिखाएं। इस प्रकार, समाज की**

**भलाई के लिए ऐसे कैदियों की मुक्ति और पुनर्वास को कारावास की सजा भुगतते समय उचित महत्व मिलना चाहिए।**

**14) उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन विभिन्न आधारों पर पैरोल दी जा सकती है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुख्य बात यह है कि एक कैदी को पारिवारिक और सामाजिक संबंध बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य से उसे कुछ समय के लिए बाहर आना होगा ताकि वह अपने पारिवारिक और सामाजिक संपर्क को बनाए रख सके। यह कारण सज़ा और सज़ा के पीछे के उद्देश्यों में से एक, अर्थात् दोषी के सुधार, में औचित्य पाता है।**अपराधशास्त्र का सिद्धांत, जिसे काफी हद तक स्वीकार किया जाता है, यह रेखांकित करता है कि राज्य अपराधी को दंडित करके जिन मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है वे हैं: निवारण, रोकथाम, प्रतिशोध और सुधार। जब हम सुधार को एक उद्देश्य के रूप में पहचानते हैं, तो यह आजीवन कारावास के दोषियों को भी थोड़े समय के लिए पैरोल पर छोड़ देने का औचित्य प्रदान करता है, ताकि ऐसे दोषियों को न केवल अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक

समस्याओं को हल करने का अवसर दिया जा सके, बल्कि समाज के साथ अपने संबंध बनाए रखने का भी अवसर दिया जा सके। एक अन्य उद्देश्य जो यह सिद्धांत रेखांकित करता है वह यह है कि ऐसे दोषियों को भी ताजी हवा में सांस लेने का अधिकार है, भले ही कुछ समय के लिए। राज्य की ओर से ये कदम, अन्य उपायों के साथ, ऐसे कैदियों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। उनका उद्देश्य अंततः 2 (2000) 3 एससीसी 394 समाज की भलाई है और इसलिए, सार्वजनिक हित में हैं।

**15) इस प्रकार, पैरोल और फर्लो के प्रावधान जेलों में बंद लोगों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ऐसे प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य उन्हें अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को हल करने का अवसर प्रदान करना और उन्हें समाज के साथ अपने संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाना है। यहां तक कि इस देश के नागरिकों का भी अपराधियों को समाज में सफल पुनः प्रवेश के लिए तैयार करने में निहित स्वार्थ है। जो लोग समर्थन के मजबूत नेटवर्क के बिना, रोजगार की**

**संभावनाओं के बिना, जिन समुदायों में वे लौटेंगे उनकी बुनियादी जानकारी के बिना और संसाधनों के बिना जेल से निकलते हैं, उनके असफल होने की संभावना काफी अधिक होती है। जब अपराधी रिहाई के बाद आपराधिक गतिविधियों में लौट आते हैं, तो वे अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें स्वीकृत नागरिकों के रूप में समाज में शामिल होने की उम्मीद नहीं होती है। फर्लो या पैरोल अपराधियों को सफलता के लिए तैयार करने में मदद कर सकती है।**

16) सजा के सुधार सिद्धांत में निहित पैरोल या फर्लो देने में उपरोक्त सार्वजनिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, किसी विशेष मामले में पैरोल या फर्लो दी जानी है या नहीं, यह तय करते समय अन्य प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नहीं। इस जनहित की मांग यह भी है कि जो आदतन अपराधी हैं और पैरोल पर छूटने के बाद दोबारा अपराध करने की प्रवृत्ति रखते हैं या समाज की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें पैरोल पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। यह पहलू सजा के अन्य

उद्देश्यों, अर्थात् निवारण और रोकथाम का ध्यान रखता है। सिक्के का यह पहलू यह अनुभव है कि बड़ी संख्या में अपराध उन अपराधियों द्वारा किए जाते हैं जिन्हें दोषसिद्धि के बाद वापस सड़क पर डाल दिया जाता है। इसलिए, यह तय करते समय कि कोई विशेष कैदी पैरोल पर रिहा होने के योग्य है या नहीं, उपरोक्त पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। संक्षेप में कहें तो, अधिकारियों को इस प्रश्न का समाधान करना चाहिए कि क्या दोषी ऐसा व्यक्ति है जिसमें इस तरह के अपराध करने की प्रवृत्ति है या वह एक अच्छा नागरिक बनने के लिए खुद को सुधारने की प्रवृत्ति दिखा रहा है।

**17) इस प्रकार, जेल में बंद सभी लोग फर्लो या पैरोल देने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जाहिर है, समाज को उन लोगों को अलग-थलग कर देना चाहिए जो पीड़ितों को शिकार बनाने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। फिर भी प्रशासकों को उन अपराधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं और जिनके व्यवहार से पता चलता है कि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में**

**जीने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार, पैरोल कार्यक्रम को ऐसे समायोजनों को आकार देने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।**

18) संक्षेप में, दंडात्मक सुधारों की शुरूआत में, राज्य जो समाज की ओर से प्रशासन चलाता है और बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के मामलों में उनकी सुरक्षा के संबंध में वैध अधिकारों की रक्षा के प्रति लापरवाह नहीं रहा जा सकता है। यही कारण है कि ऐसे सुधारों को लागू करने में, अधिकारी समाज को उन सुधारों से प्रतिरक्षित करने के दायित्व से अनभिज्ञ नहीं रह सकते हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उन्होंने किसी आपराधिक कृत्य को अंजाम देने का दोषी पाए जाने पर (न्यायालय द्वारा) आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की अपनी संवेदनशीलता साबित कर दी है। कारावास का दंड लगाने का एक स्पष्ट उद्देश्य समाज को एक निश्चित अवधि के लिए अपराधी से प्रतिरक्षा प्रदान करना है। इसलिए, यह समझने योग्य है कि दोषियों के साथ मानवीय व्यवहार करते समय, यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाना

चाहिए कि दोषियों के प्रति दयालुता का परिणाम समाज के प्रति क्रूरता न हो। स्वाभाविक रूप से, अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक होंगे कि छुट्टी पर रिहा किया गया दोषी कोई अन्य अपराध करने के अवसर का लाभ न उठाए, जब वह दंडात्मक सुधार के उपाय के रूप में उसे दी गई फर्लो छुट्टी के तहत कुछ समय के लिए फरार हो।

19) ***एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर चर्चा की जानी चाहिए वह यह है कि क्या ऐसी कोई धारणा हो सकती है कि जिस व्यक्ति को गंभीर या जघन्य अपराध का दोषी ठहराया गया है, वास्तव में, उसके साथ एक कठोर अपराधी के रूप में व्यवहार किया जाएगा। कठोर अपराधी वह व्यक्ति होगा जिसकी यह आदत या जीवनशैली बन गई है और ऐसा व्यक्ति अनिवार्य रूप से बार-बार अपराध करने की ओर प्रवृत्त होगा। जाहिर है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गंभीर अपराध किया है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है, लेकिन साथ ही यह भी पाया जाता है कि यह एकमात्र अपराध है जो उसने किया है, तो उसे कठोर अपराधी की श्रेणी में नहीं***

*रखा जा सकता है। उसके मामले में विचार इस बात पर होना चाहिए कि क्या वह खुद को सुधारने और एक अच्छा नागरिक बनने के संकेत दे रहा है या ऐसी परिस्थितियां हैं जो यह संकेत देंगी कि उसमें दोबारा अपराध करने की प्रवृत्ति है या वह समाज के लिए खतरा होगा। केवल उसके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पैरोल को सीधे तौर पर अस्वीकार करने का कारक नहीं होनी चाहिए।* जहां भी दोषी ठहराए गए व्यक्ति को लंबे समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है, उसे अस्थायी पैरोल दी जा सकती है, भले ही अपराध की प्रकृति कुछ भी हो जिसके लिए उसे सजा सुनाई गई हो। *हम यहां एक शर्त लगाने में जल्दबाजी कर सकते हैं, अर्थात उन मामलों में जहां किसी व्यक्ति को गंभीर कार्य करने के लिए दोषी ठहराया गया है, ऐसे मामलों की जांच करते समय सक्षम प्राधिकारी को सख्त मानकों को ध्यान में रखने की सलाह दी जा सकती है,उनके मामलों को ईश्वरीय आचरण, आदतन अपराधी के मापदंडों पर आंकते समय या यह निर्णय करते समय कि क्या उसे सार्वजनिक शांति और शांति आदि के लिए अत्यधिक*

***<u>खतरनाक या प्रतिकूल माना जा सकता है।</u>***

***<u>[जोर दिया गया]</u>***

उपरोक्त निर्णय का अनुपात यह है कि गंभीर या जघन्य अपराध के दोषी व्यक्ति को वास्तव में कठोर अपराधी नहीं माना जा सकता है। कठोर अपराधी वह व्यक्ति होगा जिसके लिए अपराध एक आदत या जीवन शैली बन गई है और ऐसा व्यक्ति अनिवार्य रूप से बार-बार अपराध करने की प्रवृत्ति रखता होगा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई गंभीर अपराध किया है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है, लेकिन यह पाया जाता है कि यह उसके अपराध करने का एक अकेला उदाहरण है, भले ही उसकी प्रकृति कुछ भी हो, तो उसे एक कठोर अपराधी के रूप में ब्रांडेड नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में पैरोल पर विचार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि क्या दोषी खुद में सुधार करने और एक अच्छा नागरिक बनने के लक्षण दिखा रहा है या नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो यह संकेत देंगी कि उसमें अपराध की ओर प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति है। केवल दोषी द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पैरोल को सीधे तौर पर अस्वीकार करने का कारक नहीं होनी चाहिए। किसी दिए गए मामले में, अपराध की जघन्य प्रकृति को दोषी को पैरोल से इनकार करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है यदि ऐसा

आचरण अत्यधिक खतरनाक या सार्वजनिक शांति और शांति आदि के लिए प्रतिकूल माना जाता है।

इस प्रकार, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि एक दोषी के मामले में जो लगभग 17 वर्षों तक जेल में बंद रहा है और उसने बिना किसी शिकायत के नियमित पैरोल का लाभ उठाया है, पैरोल पर उसकी रिहाई को स्पष्ट रूप से जनता, शांति या शांति आदि के प्रति प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है।

राजस्थान कैदियों को पैरोल पर रिहाई नियम 1958 का नियम 9, जो दोषी को स्थायी पैरोल पर रिहा करने के अधिकार को नियंत्रित करता है, इस प्रकार है: -

> "9. **पैरोल अवधि** - एक कैदी, जिसने अपनी सजा की एक-चौथाई सजा पूरी कर ली है और जेल में अच्छे आचरण के अधीन है, तो उसे घर और वापसी की यात्रा के दिनों सहित 20 दिनों के लिए पहली पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। और दूसरी पैरोल पर 30 दिनों के लिए, बशर्ते कि पहली पैरोल के दौरान उसका व्यवहार अच्छा रहा हो और तीसरी पैरोल पर 40 दिनों के लिए, बशर्ते कि दूसरी पैरोल के दौरान उसका व्यवहार अच्छा रहा हो। ***यदि तीसरी पैरोल के दौरान भी कैदी का***

*<u>व्यवहार अच्छा रहा हो और उसका चरित्र बहुत अच्छा रहा हो और यदि कैदी का आचरण ऐसा रहा हो कि उसके अपराध में दोबारा शामिल होने की संभावना नहीं है, उसके मामले को जेल अधीक्षक और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों पर पैरोल पर स्थायी रिहाई के लिए [राज्य समिति] के माध्यम से सरकार को सिफारिश की जा सकती है; उनमें से मुख्य शर्त यह है कि यदि कैदी पैरोल पर रहते हुए कोई अपराध करता है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाता है, उसे ऐसे अपराध के कारण उस पर लगाई गई किसी भी सजा के अलावा सजा का शेष भाग भी भुगतना होगा।</u>* ऐसे मामलों में, पैरोल पर स्थायी रिहाई अस्वीकार कर दी जाती है, कैदी अपनी सजा की शेष अवधि के लिए समान शर्तों के अधीन हर साल 40 दिनों के लिए पैरोल पर रिहाई के लिए पात्र होगा।

[उन कैदियों के मामले प्रदान किए गए हैं जिन्हें किसी ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है जिसके लिए मौत की सजा कानून द्वारा प्रदान की

गई सजाओं में से एक है या जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन इस सजा को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 433 के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, पैरोल पर स्थायी रिहाई के लिए राज्य समिति के समक्ष तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसने माफी को छोड़कर 14 साल की सजा नहीं काट ली हो, लेकिन इसमें पूछताछ, जांच या परीक्षण के दौरान पारित हिरासत की अवधि भी शामिल है। ऐसे कैदियों को ऊपर बताई गई शर्तों के अधीन उनकी सजा की शेष अवधि के लिए हर साल 40 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया जा सकता है।] **[जोर दिया गया]**

राजस्थान कैदियों को पैरोल पर रिहा करने के नियम 1958 के नियम 9 को देखने से पता चलता है कि नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंगित करता हो कि अपराध की जघन्यता या गंभीर प्रकृति किसी दोषी को पैरोल/स्थायी पैरोल से इनकार करने का वैध आधार हो सकती है।

नियम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि शब्द **"किसी कैदी को पैरोल पर रिहा करने पर विचार ऐसे दोषी को दी गई नियमित पैरोल के दौरान अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार है"।**

यदि नियमित तीसरी पैरोल के दौरान दोषी का व्यवहार उत्कृष्ट रहा हो और उसका आचरण असाधारण रूप से अच्छा रहा हो और यदि उसके दोबारा अपराध में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे दोषी का मामला स्थायी पैरोल पर रिहाई के लिए विचार करने के लिए राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार, स्थायी पैरोल देने के मानदंड को नियम में ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पैरोल आवेदन पर विचार करते समय इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस आशय का विचार पैरोल सिफारिशों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। चूंकि दोषी-याचिकाकर्ता को उसकी कैद की अवधि के दौरान नियमित रूप से पैरोल दी गई है, इसलिए यह माना जा सकता है कि जेल में और साथ ही पैरोल पर रहने के दौरान उसका आचरण उत्कृष्ट रहा है क्योंकि किसी भी तरफ से उसके खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर या कार्यवृत्त में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इसके विपरीत संकेत दे।

इस पृष्ठभूमि में, हमारी दृढ़ राय है कि दिनांक 06.07.2018 की प्रतिकूल सिफारिशें, जिसके तहत दोषी-याचिकाकर्ता श्रवण मांझी के स्थायी पैरोल पर रिहा होने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, को कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे नियमों के विपरीत हैं।

इस प्रकार, दिनांक 06.07.2018 की आक्षेपित सिफारिशों को रद्द कर दिया गया है और दोषी श्रवण मांझी को खारिज कर दिया गया है। मामला राज्य स्तरीय पैरोल समिति को भेज दिया गया है जो उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए स्थायी पैरोल देने के लिए दोषी-कैदी के मामले पर पुनर्विचार करेगी। बैठक शीघ्र बुलाई जाएगी और दोषी-याचिकाकर्ता के मामले पर अगले दो महीने के भीतर नए सिरे से फैसला किया जाएगा।

इन शर्तों के साथ रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

**न्यायाधीश, (कुमारी प्रभा शर्मा)** **न्यायाधीश, (संदीप मेहता)**

(अनुवाद एआई टूल: SUVAS के माध्यम से अनुवादक की मदद से किया गया है )

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय का उपयोग वादी को अपनी भाषा में समझने के लिए सीमित उपयोग के लिए किया जाता है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।